Pariksha Saathi — दैनिक करंट अफेयर्स

29 अक्टूबर 2026 • हिंदी

SSC CGL • CHSL • MTS • IBPS PO/Clerk • SBI PO/Clerk • RRB — 13 खबरें + 5 प्रश्न • स्रोत: PIB (सभी खबरें आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों से)

1 रबी विपणन सीजन 2027-28 के लिए एमएसपी: PIB पृष्ठभूमि टिप्पणी के अनुसार कुसुम में सबसे अधिक 675 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि

Rabi MSP for Marketing Season 2027-28: safflower gets the highest absolute increase, Rs 675 per quintal, says PIB Backgrounder

SSC • Banking • Railway • General

PIB की 29 अक्टूबर 2026 की पृष्ठभूमि टिप्पणी (बैकग्राउंडर) में रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2027-28 के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का ब्योरा दिया गया है; सरकार ने इस सीजन के लिए सभी अधिदेशित रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि को 30 सितंबर 2026 को मंज़ूरी दी थी। प्रति क्विंटल एमएसपी और 2026-27 की तुलना में वृद्धि इस प्रकार है: गेहूं 2,610 रुपये (25 रुपये की वृद्धि), जौ 2,286 रुपये (136 रुपये की वृद्धि), चना 5,958 रुपये (83 रुपये की वृद्धि), मसूर 7,390 रुपये (390 रुपये की वृद्धि), रेपसीड और सरसों 6,613 रुपये (413 रुपये की वृद्धि) और कुसुम 7,215 रुपये (675 रुपये की वृद्धि)। सबसे अधिक निरपेक्ष (एब्सोल्यूट) वृद्धि कुसुम में हुई है, उसके बाद रेपसीड और सरसों, मसूर और जौ हैं, और गेहूं व चने का एमएसपी भी बढ़ाया गया है। उत्पादन लागत पर सबसे अधिक अनुमानित मार्जिन गेहूं का 106% है, उसके बाद रेपसीड और सरसों (96%), मसूर (92%) और चना (59%) हैं; पृष्ठभूमि टिप्पणी की तालिका में जौ के लिए 58% और कुसुम के लिए 50% मार्जिन दिया गया है, और उसके अनुसार आरएमएस 2027-28 के निर्णयों में उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन का प्रावधान जारी है। आरएमएस 2027-28 के दौरान 324 लाख मीट्रिक टन उपज के लिए किसानों को अनुमानित 90,962 करोड़ रुपये का भुगतान होने की उम्मीद है। एमएसपी हर वर्ष 22 अधिदेशित फसलों के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफ़ारिशों के आधार पर घोषित किए जाते हैं। रबी की छह फसलों की खरीद 2004-05 से 2013-14 के दौरान 2,302 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) से बढ़कर 2014-15 से 2025-26 के दौरान 3,921 एलएमटी हो गई, और इनके लिए एमएसपी भुगतान 2.65 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 8.36 लाख करोड़ रुपये हो गया; आरएमएस 2026-27 में गेहूं की खरीद 357.57 एलएमटी रही, जिसका एमएसपी मूल्य 92,432.51 करोड़ रुपये था और जिससे 34 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), जिसके तहत दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद होती है, में 2025-26 सीजन से किसानों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य हो गया है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329868

2 ईएसआईसी ने नई एमनेस्टी योजना 2025 को तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 तक किया

ESIC extends the New Amnesty Scheme 2025 by three months, till 31 December 2026

SSC • Banking • General

श्रम और रोजगार मंत्रालय की 29 अक्टूबर 2026 की रिलीज़ के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने विभिन्न हितधारकों के अभ्यावेदनों की समीक्षा के बाद अपनी 'नई एमनेस्टी योजना, 2025' को, जो 01.10.2025 से 30.09.2026 तक चली, मौजूदा नियमों और शर्तों पर तीन महीने की और अवधि के लिए, यानी 01.10.2026 से 31.12.2026 तक, बढ़ा दिया है। यह योजना पूर्ववर्ती ईएसआई अधिनियम के तहत न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ घटाने और अनुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक एकमुश्त विवाद समाधान पहल है, और नियोक्ताओं को ईएसआईसी के साथ कानूनी विवादों का न्यायालय से बाहर निपटारा करने का एक व्यवस्थित तंत्र देती है। इसके तहत तदर्थ (एड-हॉक) आकलनों का निपटारा वास्तविक अंशदान और ब्याज चुकाकर किया जा सकता है और कोई क्षति (डैमेज) नहीं लगाई जाएगी; जिन मामलों में नियोक्ता अपना बकाया पहले ही चुका चुके हैं, वे विवादित क्षति के 10% के भुगतान की शर्त पर वापस लिए जाते हैं; और रिकॉर्ड जमा न करने या देर से भुगतान के लिए ईएसआईसी द्वारा दायर ऐसे मामले भी, जिनमें बाद में अनुपालन कर दिया गया, न्यायालय की अनुमति से वापस लिए जाते हैं। 31.03.2025 तक दायर न्यायालय मामले इस योजना के लिए पात्र हैं। विस्तार से पात्र नियोक्ताओं और बीमित व्यक्तियों को योजना का लाभ उठाने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा, और सभी हितधारकों से 31.12.2026 को विस्तारित अवधि समाप्त होने से पहले इसका उपयोग करने का आग्रह किया गया है। रिलीज़ के अनुसार यह योजना विवाद समाधान का एक व्यावहारिक और नियोक्ता-हितैषी रास्ता है, जो व्यापार सुगमता बढ़ाने के सरकार के व्यापक लक्ष्य में सहायक है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329854

3 सेबू में 13वीं एडीएमएम-प्लस में रक्षा मंत्री: भारत सामूहिक क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध, साझेदारों के साथ धरातल पर परखा गया अनुभव साझा करने को तैयार

Raksha Mantri at the 13th ADMM-Plus in Cebu: India committed to collective regional security and eradication of terrorism, ready to share battle-tested expertise with partners

SSC • Railway • Defence • General

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 अक्टूबर 2026 को फिलीपींस के सेबू में 13वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) को संबोधित करते हुए आतंकवाद के सभी रूपों के उन्मूलन और सामूहिक क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि आतंकवाद-रोधी अभियानों में भारत का व्यापक अनुभव कक्षा तक सीमित सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, बल्कि सीमा पार की जटिल सुरक्षा चुनौतियों का दशकों तक सीधे सामना करके धरातल पर अर्जित किया गया अनुभव है, और भारत के इस सक्रिय और धरातल पर परखे गए सिद्धांत का निर्णायक प्रदर्शन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ, जब भारत ने आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त किया और राज्य प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध समझौता न करने वाली स्पष्ट सीमा (रेड लाइन) लागू की। यह कहते हुए कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती, उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अभ्यासों, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और व्यापक खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान के माध्यम से एडीएमएम-प्लस के साझेदारों के साथ अपना व्यावहारिक, धरातल पर परखा हुआ अनुभव साझा करने के लिए पूरी तरह तैयार है; एडीएमएम-प्लस प्रारूप के अंतर्गत आतंकवाद-रोधी सहयोग एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है, और भारत तथा मलेशिया 2024 से 2027 की अवधि के लिए आतंकवाद-रोधी विशेषज्ञ कार्य समूह की सह-अध्यक्षता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैठक की विषयवस्तु 'नेविगेटिंग अवर फ्यूचर, टुगेदर' भारत की सभ्यतागत भावना 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' (सभी सुखी हों) से सामंजस्य रखती है। 2026 के दौरान आसियान के साथ भारत के जुड़ाव में समुद्री सहयोग को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने 2026 को 'आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष' घोषित किए जाने और दूसरे आसियान-भारत समुद्री अभ्यास के आयोजन का उल्लेख किया, बताया कि भारतीय नौसेना 2008 से अदन की खाड़ी जैसे अत्यंत संवेदनशील समुद्री गलियारों में लगातार सक्रिय उपस्थिति बनाए हुए है, और कहा कि कानून के शासन, विशेष रूप से समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनसीएलओएस), पर भारत का आग्रह तथा नौवहन और उड़ान (ओवरफ़्लाइट) की स्वतंत्रता का समर्थन किसी देश के विरुद्ध नहीं है। उन्होंने संस्थागत स्तर पर लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने, डिजिटल नवाचार को प्रोत्साहित करने और एडीएमएम-प्लस की पहलों के अनुरूप क्षमता निर्माण को सुगम बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र में एक समर्पित 'यूथ ब्रिज' स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329874

4 सी. आर. पाटिल ने नई दिल्ली में गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की; बोर्ड ने गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के संशोधित कार्यादेश और पुनर्गठन पर विचार-विमर्श किया

C. R. Patil chairs the 19th meeting of the Ganga Flood Control Board in New Delhi; Board deliberates on the revised mandate and restructuring of the Ganga Flood Control Commission

SSC • Railway • Environment • General

जल शक्ति मंत्रालय ने 29 अक्टूबर 2026 को बताया कि गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड (जीएफसीबी) की 19वीं बैठक 27 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री राम नाथ ठाकुर, नीति आयोग के सदस्य प्रो. के. वी. राजू, बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ गंगा बेसिन राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जीएफसीबी का गठन भारत सरकार ने 18 अप्रैल 1972 को गंगा बेसिन में बाढ़, कटाव और जल निकासी की समस्याओं से निपटने के उपायों की समन्वित योजना बनाने और उनके क्रियान्वयन को सुगम बनाने के लिए किया था; इसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री करते हैं, इसमें संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि और गंगा बेसिन राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि शामिल होते हैं, और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) के अध्यक्ष इसके सदस्य सचिव होते हैं। बैठक में मंत्री ने 'पुनः भरण मोबाइल ऐप' का शुभारंभ किया, जिसे भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान ने राष्ट्रीय जल मिशन के सहयोग से विकसित किया है और जिसका उद्देश्य भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए उपयुक्त स्थलों की वैज्ञानिक पहचान में सहायता करना है। बोर्ड ने जीएफसीसी के संशोधित कार्यादेश और पुनर्गठन पर विचार-विमर्श किया, जिसमें बेसिन स्तर पर बाढ़ प्रबंधन योजना को सुदृढ़ करना, बाढ़ प्रबंधन योजनाओं का मूल्यांकन, नदी की आकृति (मॉर्फोलॉजी) एवं अवसादन संबंधी अध्ययन और बाढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफएमआईएस) का विकास शामिल है, और चर्चा में जोखिम-आधारित बेसिन मास्टर प्लान, पुलों के नीचे जलमार्गों और जल-निकास मार्गों (वेंटवे) की पर्याप्तता के आकलन, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) की गुणवत्ता में सुधार और बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन पर ध्यान दिया गया।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329935

5 अक्टूबर 2026 तक 5.5 लाख एमटीपीए से अधिक की हरित हाइड्रोजन ऑफटेक प्रतिबद्धताओं के साथ भारत विश्व में अग्रणी; 2026 में 18 नए समझौते

India leads globally with Green Hydrogen offtake commitments of over 5.5 lakh MTPA till October 2026; 18 new agreements signed in 2026

SSC • Banking • Environment • General

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने 29 अक्टूबर 2026 को बताया कि अक्टूबर 2026 तक भारतीय कंपनियों ने दुनिया की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन ऑफटेक (खरीद) प्रतिबद्धताएँ की हैं, जो कुल 5.5 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से अधिक हैं, और इससे भारत हरित हाइड्रोजन आपूर्ति प्रतिबद्धताओं में विश्व में अग्रणी बन गया है। अक्टूबर 2026 तक भारतीय कंपनियों की पक्की और हस्ताक्षरित प्रतिबद्धताएँ 5,55,610 एमटीपीए तक पहुँच गई थीं, जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) के लक्ष्य का लगभग 11% है। केवल 2026 में भारतीय कंपनियों ने 4 लाख एमटीपीए से अधिक हरित हाइड्रोजन समतुल्य मात्रा की आपूर्ति के लिए 18 नए ऑफटेक समझौते किए; 2023 में मिशन की शुरुआत के बाद से लगभग 5.5 लाख एमटीपीए हरित हाइड्रोजन समतुल्य के कुल 23 ऑफटेक अनुबंध हुए हैं, जिनमें से 70% से अधिक निर्यात के लिए निर्धारित हैं। इन परियोजनाओं से लगभग ₹90,000 करोड़ (लगभग 9.5 अरब अमेरिकी डॉलर) का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। मंत्रालय द्वारा बताए गए अनुबंधों में एसीएमई ग्रुप (ACME Group) के जापान की आईएचआई (IHI) को 4,88,000 एमटीपीए हरित अमोनिया और जापान की मित्सुबिशी गैस केमिकल (MGC) को 1,00,000 एमटीपीए हरित मेथनॉल की आपूर्ति के समझौते; दक्षिण कोरिया की सैमसंग सी एंड टी कॉरपोरेशन (Samsung C&T Corporation) के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 3 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य का दीर्घकालिक आपूर्ति और खरीद समझौता, जो दुनिया के सबसे बड़े हरित अमोनिया ऑफटेक अनुबंधों में से एक है; और एएम ग्रीन (AM Green) का HINT.CO GmbH द्वारा चलाई गई एच2ग्लोबल (H2Global) नीलामी के एशियाई लॉट में एकमात्र विजेता के रूप में चयन शामिल है, जिसके तहत हिंटको (Hintco) 10 वर्षों में कम से कम 585 मिलियन यूरो मूल्य का आरएफएनबीओ (गैर-जैविक मूल के नवीकरणीय ईंधन) अमोनिया एएम ग्रीन से खरीदेगी, और जर्मनी को पहली आपूर्ति 2029 में होने की उम्मीद है। देश के भीतर, मिशन के 'स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन' (एसआईजीएचटी) कार्यक्रम के तहत देश भर की 11 उर्वरक इकाइयों को 6,70,000 एमटीपीए हरित अमोनिया के उत्पादन और आपूर्ति के समझौते हुए हैं, और आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और एनआरएल की रिफाइनरियों को 30,000 एमटीपीए हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और आपूर्ति की परियोजनाएँ दी गई हैं। मंत्रिमंडल द्वारा 2029-30 तक ₹19,744 करोड़ के प्रारंभिक परिव्यय के साथ स्वीकृत इस मिशन का उद्देश्य 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटीपीए) हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329940

6 भारत के क्लाउड इकोसिस्टम पर PIB पृष्ठभूमि टिप्पणी: 2014 में शुरू हुए मेघराज को 2,330 सरकारी विभागों ने अपनाया; 30 क्लाउड सेवा प्रदाता सूचीबद्ध

PIB Backgrounder on India's cloud ecosystem: MeghRaj, launched in 2014, adopted by 2,330 government departments; 30 cloud service providers empanelled

SSC • Banking • Science • General

PIB की 29 अक्टूबर 2026 की पृष्ठभूमि टिप्पणी 'भारत में क्लाउड इकोसिस्टम' (Cloud Ecosystem in India) के अनुसार क्लाउड कंप्यूटिंग डिजिटल शासन और सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी का एक महत्वपूर्ण आधार बन रही है, और घरेलू क्लाउड महत्वपूर्ण डिजिटल संसाधनों पर राष्ट्रीय नियंत्रण मज़बूत करके डेटा संप्रभुता में सहायक हो सकता है। भारत सरकार का क्लाउड इकोसिस्टम मेघराज 2014 में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने ई-गवर्नेंस को गति देने और सार्वजनिक आईसीटी व्यय को अनुकूलित (ऑप्टिमाइज़) करने के लिए शुरू किया था; इस राष्ट्रीय क्लाउड कंप्यूटिंग पहल का दूसरी पीढ़ी का संस्करण मेघराज 2.0 वितरित (डिस्ट्रिब्यूटेड) क्लाउड संरचना के माध्यम से IaaS, PaaS और SaaS मॉडल देता है और डिजिलॉकर, माईगव, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल और डाक विभाग की एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी (एपीटी) जैसे प्लेटफ़ॉर्म के लिए होस्टिंग देता है। सितंबर 2026 तक इस इकोसिस्टम को अपनाने वाले सरकारी विभागों की संख्या 2,330 हो गई थी। सितंबर 2026 तक भारत ने 30 क्लाउड सेवा प्रदाताओं (सीएसपी) को सूचीबद्ध (एम्पैनल) किया था। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) देश भर में 4 राष्ट्रीय डेटा केंद्र और 24 मिनी डेटा केंद्र चलाता है, और अगस्त 2026 तक भारत की डेटा सेंटर क्षमता 1.57 गीगावाट तक पहुँच गई थी, जिसके 2030 तक लगभग 8 गीगावाट तक बढ़ने का अनुमान है। मार्च 2026 में MeitY ने मंत्रालयों और विभागों को डेटा की संवेदनशीलता और महत्व (क्रिटिकैलिटी) के आधार पर क्लाउड अवसंरचना चुनने में मार्गदर्शन के लिए एक क्लाउड चयन ढाँचा (क्लाउड सिलेक्शन फ्रेमवर्क) जारी किया। डिजिटल इंडिया भाषिणी प्लेटफ़ॉर्म योटा डेटा सर्विसेज द्वारा संचालित एक भारतीय क्लाउड पर स्थानांतरित हो गया है, जिससे उसके भाषा डेटासेट, एआई मॉडल और नागरिकों के साथ संवाद भारत के अधिकार क्षेत्र में रहते हैं। ₹10,371.92 करोड़ के परिव्यय के साथ स्वीकृत इंडियाएआई मिशन के तहत एक साझा एआई कंप्यूटिंग सुविधा के लिए 45,000 से अधिक ग्राफ़िक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) जोड़े गए हैं, और MeitY-नैसकॉम द्वारा 2021 में शुरू किए गए फ्यूचरस्किल्स प्राइम कार्यक्रम में अगस्त 2026 तक 34 लाख पंजीकृत अभ्यर्थी थे।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329978

7 आयुष्मान वय वंदना के दो वर्ष पूरे: 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹5,668.80 करोड़ मूल्य की 23.46 लाख अधिकृत अस्पताल भर्तियाँ

Ayushman Vay Vandana completes two years: 23.46 lakh authorised hospital admissions worth ₹5,668.80 crore for senior citizens aged 70 and above

SSC • Railway • General

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि आयुष्मान वय वंदना, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के हर नागरिक तक, उसकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, पहुँचाती है, 29 अक्टूबर 2026 को दो वर्ष पूरे कर चुकी है। प्रधानमंत्री द्वारा 29 अक्टूबर 2024 को शुरू की गई और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा लागू की जा रही यह पहल लगभग 4.5 करोड़ परिवारों के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों तक स्वास्थ्य कवरेज बढ़ाने और उनकी वित्तीय सुरक्षा मज़बूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक के स्वास्थ्य कवर के पात्र हैं; एबी पीएम-जेएवाई में पहले से शामिल परिवारों के ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को केवल अपने लिए प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर मिलता है, जो परिवार के 70 वर्ष से कम आयु के सदस्यों को मिलने वाले कवर से अलग है। 20 अक्टूबर 2026 तक इस पहल के तहत 23.46 लाख अधिकृत अस्पताल भर्तियाँ दर्ज हुई थीं, जिनका कुल मूल्य ₹5,668.80 करोड़ है। सबसे अधिक बार ली गई प्रक्रिया मोतियाबिंद सर्जरी है, जिसके 4.71 लाख उपचार हुए, जो सभी अधिकृत उपचारों का लगभग 20.1 प्रतिशत हैं, और इसके बाद क्रोनिक हीमोडायलिसिस है, जिसके लगभग 2.90 लाख उपचार हुए; अधिकृत मूल्य के हिसाब से सबसे बड़ा हिस्सा परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी (पीटीसीए) का है, लगभग ₹649 करोड़। उपचार की अन्य प्रमुख श्रेणियों में घुटना प्रत्यारोपण (टोटल नी रिप्लेसमेंट), क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिज़ीज़ (सीओपीडी) के तीव्र प्रकोप का प्रबंधन, तीव्र ज्वर संबंधी बीमारी, और तीव्र किडनी क्षति व गुर्दे की विफलता शामिल हैं। एनएचए के सीईओ डॉ. सुनील कुमार बर्णवाल ने इस पहल को एक अधिक समावेशी स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जो यह सुनिश्चित करती है कि वित्तीय तंगी वरिष्ठ नागरिकों के ज़रूरी अस्पताल उपचार में बाधा न बने।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2330009

8 भारत से अंताल्या तक: नई दिल्ली में दूसरे एराइज़ सिटीज़ फ़ोरम के समापन पर स्वीकृत दिल्ली घोषणापत्र 2026 में कॉप31 से पहले बहुस्तरीय जलवायु कार्रवाई को मज़बूत करने का आह्वान

From Bharat to Antalya: Delhi Declaration 2026, adopted at the close of the second ARISE Cities Forum in New Delhi, calls for stronger multilevel climate action ahead of COP31

SSC • Railway • Environment • General

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि एराइज़ सिटीज़ फ़ोरम 2026 का समापन 28 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में 'वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के लिए स्थानीय कार्रवाई पर दिल्ली घोषणापत्र' (Delhi Declaration on Local Action for Global Climate Goals) की स्वीकृति के साथ हुआ। 27-28 अक्टूबर 2026 को इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुए इस फ़ोरम के दूसरे संस्करण का आयोजन आईसीएलईआई दक्षिण एशिया ने राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (एनआईयूए) के सहयोग से और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के समर्थन से किया। इसमें 18 से अधिक देशों के 50 से अधिक शहरों से 200 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए, और इसमें तीन तकनीकी प्लेनरी सत्र और 14 तकनीकी सत्र हुए। 'भारत से अंताल्या तक - प्रतिबद्धता। क्रियान्वयन। परिणाम' (From Bharat to Antalya - Commit. Implement. Deliver) विषय पर आधारित इस फ़ोरम ने ग्लोबल साउथ के शहरों और स्थानीय सरकारों की ओर से मज़बूत बहुस्तरीय सहयोग और वैश्विक जलवायु शासन में उन्हें अपरिहार्य भागीदार के रूप में मान्यता देने का एकजुट आह्वान किया; दिल्ली घोषणापत्र 2026 में व्यक्त यह सामूहिक महत्वाकांक्षा अब तुर्किये के अंताल्या में होने वाले कॉप31 तक जाएगी। फ़ोरम का समापन घोषणापत्र की स्वीकृति और आईसीएलईआई के महासचिव गिनो वैन बेगिन को उसके औपचारिक हस्तांतरण के साथ हुआ। 2025 के घोषणापत्र को आगे बढ़ाते हुए यह घोषणापत्र शहरों को अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करता है, ग्लोबल साउथ के अनुभवों और प्राथमिकताओं को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) की प्रक्रिया में लाता है, और दस साझा प्रतिबद्धताएँ तय करता है, जिनमें बहुस्तरीय जलवायु वित्त को संस्थागत रूप देना और 1.5 डिग्री सेल्सियस के मार्ग पर लौटने के लिए उप-राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन को मान्यता देने और गति देने वाला ऊर्जा संक्रमण परिणाम हासिल करना शामिल हैं। रिलीज़ के अनुसार 2026 'ट्रिपल कॉप' वर्ष है, इसलिए यह घोषणापत्र जलवायु, जैव विविधता और भूमि से जुड़े एजेंडों पर समन्वित कार्रवाई का आह्वान भी है। समापन समारोह में आईसीएलईआई दक्षिण एशिया द्वारा विकसित दिल्ली जैव विविधता मानचित्र (Delhi Biodiversity Map) भी जारी किया गया।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2330002

9 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अगस्त 2026 के लिए 19 उप-क्षेत्रों का उप-क्षेत्रीय ट्रायल सेवा उत्पादन सूचकांक (आईएसपी) जारी किया, आधार वर्ष 2024-25

MoSPI releases the Sub-Sectoral Trial Index of Services Production (ISP) for August 2026 for 19 sub-sectors, with base year 2024-25

SSC • Banking • General

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने 29 अक्टूबर 2026 को अगस्त 2026 के लिए 19 उप-क्षेत्रों का सेवा उत्पादन सूचकांक (आईएसपी) जारी किया, जिसका आधार वर्ष 2024-25 है। मासिक आईएसपी प्रायोगिक आधार पर, एक ट्रायल (परीक्षण) श्रृंखला के रूप में प्रकाशित किए जा रहे हैं: मंत्रालय के अनुसार ट्रायल श्रृंखला के प्रकाशन से उसे डेटा की गुणवत्ता की जाँच करने, श्रृंखला की मज़बूती (रेज़िलिएंस) परखने और हितधारकों व उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अगस्त 2025 की तुलना में अगस्त 2026 में खुदरा व्यापार में 19.9 प्रतिशत, मरम्मत सेवाओं और रियल एस्टेट दोनों में 17.6 प्रतिशत, बीमा में 16.5 प्रतिशत, बैंकिंग में 14.9 प्रतिशत, थोक व्यापार में 10.2 प्रतिशत और रेल परिवहन में 3.7 प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि वायु परिवहन (-9.6 प्रतिशत) और कला, मनोरंजन और मनोविनोद सेवाओं (-4.7 प्रतिशत) में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई। रेलवे, बैंकिंग और बीमा उप-क्षेत्रों के सूचकांक अनंतिम मासिक आंकड़ों पर आधारित हैं और इनमें वार्षिक आधार पर संशोधन किया जाएगा। रिलीज़ में अगस्त 2025 से 19 उप-क्षेत्रों के माहवार ट्रायल सूचकांक भी दिए गए हैं, और आईएसपी के आंकड़े मंत्रालय के ई-सांख्यिकी पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2330036

10 प्रमुख बंदरगाहों के लिए न्यायिक बोर्ड ने कोच्चि में कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण में ई-फाइलिंग पोर्टल शुरू किया और उपयोगकर्ता पुस्तिका जारी की

Adjudicatory Board for Major Ports launches e-Filing Portal and releases User Manual at Cochin Port Authority, Kochi

SSC • Railway • General

प्रमुख बंदरगाहों के लिए न्यायिक बोर्ड (एडजुडिकेटरी बोर्ड फॉर मेजर पोर्ट्स, एबीएमपी) ने 29 अक्टूबर 2026 को कोच्चि में कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण में अपना ई-फाइलिंग पोर्टल औपचारिक रूप से शुरू किया और उसकी उपयोगकर्ता पुस्तिका (यूज़र मैनुअल) जारी की। यह बोर्ड के डिजिटल परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसका उद्देश्य बोर्ड के समक्ष मामले दाखिल करने और उनके प्रबंधन के लिए एक पारदर्शी, कुशल और उपयोगकर्ता-अनुकूल व्यवस्था बनाना है। कार्यक्रम में एबीएमपी के पीठासीन अधिकारी, केरल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशीष जे. देसाई, और इसके सदस्य, उपभोक्ता मामले विभाग के पूर्व सचिव चिर्रावुरी विश्वनाथ और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पूर्व सचिव डॉ. संजीव रंजन उपस्थित रहे; कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सतीश होन्नक्कट्टे भी मौजूद थे, जबकि पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पत्तन और पीपीपी) प्रवीण पी. नायर, कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. एम. अंगमुथु और अन्य प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों, पीपीपी रियायतग्राहियों, बंदरगाह उपयोगकर्ताओं और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुए। यह पोर्टल मामलों को ऑनलाइन दाखिल करने और मामलों से जुड़ी गतिविधियों की डिजिटल प्रोसेसिंग और प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है, और ई-कोर्ट सुविधाओं से इसके एकीकरण का उद्देश्य हाइब्रिड सुनवाई में सहायता करना है; उपयोगकर्ता पुस्तिका पोर्टल के इस्तेमाल का चरण-दर-चरण मार्गदर्शन देती है, और पोर्टल तथा डिजिटल केस प्रबंधन प्रणाली का लाइव प्रदर्शन भी किया गया। एबीएमपी का गठन केंद्र सरकार ने 13 अगस्त 2025 को महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के तहत किया था, ताकि वह इस अधिनियम के तहत उसे सौंपे गए न्यायिक निर्णय संबंधी और अन्य कार्य कर सके। यह शुरुआत प्रमुख बंदरगाह क्षेत्र में डिजिटल शासन, व्यापार सुगमता (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस) और विवादों के कुशल समाधान के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के प्रति बोर्ड की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2330017

11 अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 14वें अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन; 22 देशों के 43 अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के साथ आईटीएम में अब तक की सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय खरीदार भागीदारी

14th International Tourism Mart inaugurated in Tawang, Arunachal Pradesh; 43 international buyers from 22 countries mark the highest-ever international buyer participation at ITM

SSC • Railway • General

पर्यटन मंत्रालय ने बताया कि उसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश सरकार और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के सहयोग से आयोजित अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट (आईटीएम) का 14वां संस्करण 29 अक्टूबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में शुरू हुआ। 29 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले इस तीन दिवसीय मार्ट का उद्देश्य आठ पूर्वोत्तर राज्यों की पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करना और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय पर्यटन बाज़ारों के साथ व्यावसायिक जुड़ाव को मज़बूत करना है। उद्घाटन सत्र केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत; पर्यटन एवं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी; शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर) राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार; अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू; और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की उपस्थिति में हुआ। शेखावत ने बताया कि इस मार्ट में 22 देशों के 43 अंतरराष्ट्रीय खरीदार आए हैं, जो आईटीएम में अब तक की सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय खरीदार भागीदारी है, साथ ही 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 42 घरेलू खरीदार और 81 विक्रेता भी शामिल हैं, और आठ पूर्वोत्तर राज्यों में घरेलू पर्यटकों की यात्राएँ 2019 के 95.65 लाख से बढ़कर 2025 में 1.51 करोड़ हो गईं, यानी लगभग 58% की वृद्धि। क्षेत्र में पर्यटन अवसंरचना और कनेक्टिविटी पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि स्वदेश दर्शन 1.0 के तहत ₹1,309 करोड़ की 16 परियोजनाएँ और स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत ₹564 करोड़ की 17 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं, इनके अलावा चुनौती आधारित गंतव्य विकास, एसएएससीआई और प्रसाद के तहत भी परियोजनाएँ स्वीकृत हैं, और मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ान के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में दस पर्यटन मार्गों को सहायता दी है। कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा और अन्य सांस्कृतिक उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले नॉर्थ ईस्ट बाजार का उद्घाटन किया गया, और 30 अक्टूबर 2026 को पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन मंत्रियों की एक क्षेत्रीय बैठक होगी। 14वें संस्करण के साथ आईटीएम 13 वर्ष बाद तवांग लौटा है; इससे पहले 2013 में इसका दूसरा संस्करण यहीं हुआ था।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2330273

12 आईएनएस त्रिशूल ने भूमध्य सागर में परिचालन तैनाती के दौरान इटली के सिविटावेचिया में पोर्ट कॉल का समापन किया

INS Trishul concludes port call at Civitavecchia, Italy, during her operational deployment in the Mediterranean Sea

SSC • Railway • Defence • General

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय नौसेना के जहाज त्रिशूल ने भूमध्य सागर में अपनी मौजूदा परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में 28 अक्टूबर 2026 को इटली के सिविटावेचिया में अपनी पोर्ट कॉल का समापन किया। इस पोर्ट कॉल ने पेशेवर बातचीत, क्रॉस-डेक यात्राओं और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से भारतीय नौसेना और इतालवी नौसेना के बीच समुद्री जुड़ाव को और मज़बूत करने का अवसर दिया। आईएनएस त्रिशूल के कमांडिंग ऑफिसर ने इतालवी नौसेना के फ्लीट कमांडर से मुलाकात की, और जहाज के चालक दल ने सिविटावेचिया में इतालवी नौसेना के विमानवाहक पोत आईटीएस कैवोर का दौरा किया; जहाज को आगंतुकों के लिए भी खोला गया, जिससे बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी और स्थानीय लोग आकर्षित हुए। इटली में भारत की राजदूत वाणी राव और इतालवी नौसेना के फ्लीट कमांडर और सीआईएनसीएनएवी वाइस एडमिरल ऑरेलियो डी कैरोलिस ने आईएनएस त्रिशूल का दौरा कर चालक दल से बातचीत की, और जहाज पर आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें सिविटावेचिया के मेयर, इतालवी नौसेना और तटरक्षक बल के वरिष्ठ अधिकारी, 13 देशों के रक्षा दूत, नागरिक गणमान्य व्यक्ति और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य एक साथ आए। मंत्रालय के अनुसार इस पोर्ट कॉल ने भारत और इटली के बीच स्थायी समुद्री साझेदारी को दर्शाया; आईएनएस त्रिशूल अब भूमध्य सागर में अपनी परिचालन तैनाती के अगले चरण के लिए रवाना हो गया है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2330070

13 अमित शाह की अध्यक्षता में एनसीडीसी की महापरिषद की 93वीं बैठक; वित्त वर्ष 2025-26 में एनसीडीसी का शुद्ध लाभ ₹1,475 करोड़, ऋण वसूली दर 99.84 प्रतिशत और नेट एनपीए शून्य

Amit Shah chairs 93rd meeting of NCDC's General Council; NCDC records net profit of ₹1,475 crore, loan recovery rate of 99.84 per cent and zero net NPA in FY 2025-26

SSC • Banking • General

सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की महापरिषद की 93वीं बैठक 29 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित निगम के मुख्यालय में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। शाह ने कहा कि एनसीडीसी ने पिछले लगभग पाँच वर्षों में अत्यंत सराहनीय प्रदर्शन किया है और इस बात पर विशेष संतोष व्यक्त किया कि निगम ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अपनी उपस्थिति स्थापित कर ली है; उन्होंने एनसीडीसी को अगले 25 वर्षों के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया और कहा कि इसके लिए सहकारी क्षेत्र के अनुभवी प्रतिनिधियों और पेशेवर विशेषज्ञों का एक समूह गठित किया जाना चाहिए, जो निगम की वर्तमान संरचना, पूँजी जुटाने के वैकल्पिक माध्यमों, वित्तीय स्वायत्तता और संगठनात्मक सुधारों पर विचार करे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक पूर्वोत्तर को दूध, अंडा, मछली और मांस के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और एनसीडीसी के पूर्वोत्तर स्थित कार्यालयों को इन क्षेत्रों में व्यावहारिक परियोजनाएँ तैयार करने का निर्देश दिया; उन्होंने नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों के साथ कंसोर्टियम और सह-वित्तपोषण मॉडल विकसित करने का सुझाव भी दिया। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹1.70 लाख करोड़, 2027-28 के लिए ₹2.10 लाख करोड़ और 2028-29 के लिए ₹2.50 लाख करोड़ के संवितरण लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने आगामी वर्षों के लिए और अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करने को कहा। बैठक में प्रस्तुत वित्तीय विवरणों के अनुसार, सहकारिता मंत्रालय के गठन से 25 अक्टूबर 2026 तक एनसीडीसी ने सहकारी संस्थाओं को संचयी रूप से ₹4,14,586 करोड़ की वित्तीय सहायता वितरित की है। वित्त वर्ष 2025-26 में निगम ने ₹1,55,408 करोड़ की परियोजनाएँ स्वीकृत कीं, ₹1,27,596 करोड़ वितरित किए और ₹1,475 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जबकि उसकी ऋण वसूली दर 99.84 प्रतिशत और नेट एनपीए शून्य रहा; उसका वार्षिक संवितरण वित्त वर्ष 2020-21 के ₹24,733 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में ₹1,27,596 करोड़ हो गया, यानी लगभग पाँच गुना वृद्धि। बैठक में 14 अगस्त 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 2026 के महत्व पर भी चर्चा हुई; केंद्र सरकार ने एनसीडीसी के लिए ₹2,000 करोड़ की अनुदान सहायता को मंज़ूरी दी है, जिसके आधार पर निगम ने चार वर्षों में बाज़ार से ₹20,000 करोड़ जुटाने की व्यवस्था की है। एनसीडीसी की 'सहकार नवाचार योजना' के तहत पात्र सहकारी संस्थाओं को अधिकतम ₹25 लाख तक की 100 प्रतिशत (शत-प्रतिशत) अनुदान सहायता दी जाती है; इसके लिए ₹10 करोड़ का प्रारंभिक निधि कोष बनाया गया है, जिसमें से 20 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों और कमज़ोर वर्गों की सहकारी संस्थाओं के लिए आरक्षित है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2330122

आज का अभ्यास — 5 प्रश्न

प्र.1 वित्त मंत्रालय की खातों की मासिक समीक्षा के अनुसार, सितंबर 2026 तक भारत सरकार को 2026-27 के बजट अनुमान (BE) की कुल प्राप्तियों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ?

(A) 47.7%
(B) 50.3%
(C) 49.5%
(D) 53.4%

प्र.2 तंदूर रेडग्राम, जिसकी ऑस्ट्रेलिया को पहली निर्यात खेप अक्टूबर 2026 में एपीडा के सहयोग से रवाना हुई, किस राज्य का पहला कृषि उत्पाद है जिसे भौगोलिक संकेतक (जीआई) पंजीकरण मिला?

(A) महाराष्ट्र
(B) कर्नाटक
(C) आंध्र प्रदेश
(D) तेलंगाना

प्र.3 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा पहला बिम्सटेक समुद्री सुरक्षा अभ्यास, "समृद्ध, सुदृढ़ और खुले बिम्सटेक" (BIMSTEC: Prosperous, Resilient and Open) की विषय-वस्तु के तहत आयोजित किस बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के परिणामों को आगे बढ़ाता है?

(A) छठे
(B) सातवें
(C) चौथे
(D) पाँचवें

प्र.4 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित ट्राई के दूरसंचार सदस्यता आँकड़ों की मुख्य बातों के अनुसार, सितंबर 2026 के अंत में भारत में कुल टेलीफोन ग्राहकों (वायरलेस + वायरलाइन) की संख्या कितनी थी?

(A) 1212.80 मिलियन
(B) 1319.19 मिलियन
(C) 1367.93 मिलियन
(D) 1412.36 मिलियन

प्र.5 31 अक्टूबर 2026 को गुजरात के एकता नगर में मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभभाई पटेल की कौन-सी जयंती के उपलक्ष्य में था?

(A) 151वीं
(B) 152वीं
(C) 150वीं
(D) 149वीं

उत्तर: 1-(B) 2-(D) 3-(A) 4-(C) 5-(A)

रोज़ सुबह 7 बजे यही PDF Telegram पर: t.me/parikshasaathiapp — चैनल से जुड़ें और दोस्तों को भेजें

रोज़ का PDF: parikshasaathi.com/daily-pdf — सभी संस्करण: parikshasaathi.com/downloads/

वेबसाइट: parikshasaathi.com (हिंदी + English में 248 पाठ, रोज़ का करंट अफेयर्स, परीक्षा नोटिस)

ऐप: Pariksha Saathi — Free, Offline, SSC/Bank की पूरी तैयारी। प्रकाशक: Mahesh Srivastava, Founder. सामग्री आधिकारिक विज्ञप्तियों से AI की सहायता से तैयार; किसी विषय-विशेषज्ञ संपादक द्वारा समीक्षित नहीं। ग़लती दिखे तो parikshasaathi.com/contact/ पर बताएँ।